उत्तर प्रदेश से निर्यात :

रुझान, अवसर और नीतिगत परिप्रेक्ष्य

भारतीय निर्यात–आयात बैंक

उत्तर प्रदेश से निर्यात: रुझान, अवसर और नीतिगत परिप्रेक्ष्य

यह अध्ययन बैंक द्वारा किए गए शोध अध्ययनों के निष्कर्षों को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। शोध अध्ययनों के परिणाम निर्यातकों, नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों, निर्यात संवर्धन एजेंसियों के साथ–साथ शोधकर्ताओं की रुचि के हो सकते हैं। तथापि, आवश्यक नहीं कि शोध अध्ययन में अभिव्यक्त विचार बैंक के ही हों। हालांकि सूचना और आंकड़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है, तथापि ऐसी मदों की प्रामाणिकता, शुद्धता या पूर्णता के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

© भारतीय निर्यात–आयात बैंक
फरवरी 2023

विषय सूची

	पृष्ठ सं.

चार्ट सूची	v
तालिकाओं की सूची	vii
1. परिचय	1
2. प्रमुख आर्थिक गतिविधियां	3
3. निर्यात परिदृश्य	8
4. उत्तर प्रदेश की निर्यात तत्परता का तुलनात्मक मूल्यांकन	18
5. उत्तर प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए रणनीति	19
6. निष्कर्ष	33
अनुलग्नक 1: उत्तर प्रदेश के लिए शीर्ष 10 उत्पाद चैंपियन के शीर्ष निर्यात गंतव्य और शीर्ष आयातक	34

परियोजना टीम:

सुश्री जाह्नवी सिंह, मुख्य प्रबंधक, शोध एवं विश्लेषण समूह

सुश्री नेहा रामन, उप प्रबंधक, शोध एवं विश्लेषण समूह

श्री अशोक सिंह, अधिकारी, शोध एवं विश्लेषण समूह

अनुवाद:

श्री कुणाल गुलाटी, मुख्य प्रबंधक, कॉर्पोरेट संचार समूह

चार्ट सूची

शीर्षक		पृष्ठ क्र.

चार्ट 1:	उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेट्रिक्स	2
चार्ट 2:	उत्तर प्रदेश के स्थिर मूल्यों (2011–12) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में रुझान	3
चार्ट 3:	क्षेत्र–वार जीएसवीए संरचना	4
चार्ट 4:	उत्तर प्रदेश से वस्तु निर्यातों में रुझान	8
चार्ट 5:	उत्तर प्रदेश से वस्तु निर्यातों के लिए शीर्ष गंतव्य (2021-22)	9
चार्ट 6:	उत्तर प्रदेश से निर्यातित शीर्ष उत्पाद (2021-22)	10
चार्ट 7:	उत्तर प्रदेश से निर्यात के लिए उत्पादों का चिह्नीकरण (2021)	15
चार्ट 8:	बंदरगाह विहीन राज्यों और सर्वश्रेष्ठ निष्पादन वाले राज्यों के साथ ईपीआई पर उत्तर प्रदेश की तुलना	18
चार्ट 9:	ईपीआई के परिवहन कनेक्टिविटी पैरामीटर पर उत्तर प्रदेश का स्कोर	29
चार्ट 10:	राज्य–वार परिवहन कनेक्टिविटी स्कोर	30

तालिकाओं की सूची

शीर्षक		पृष्ठ क्र.
तालिका 1:	भारत के निर्यातों में उच्चतम हिस्सेदारी वाले उत्पाद (2021-22)	11
तालिका 2:	उत्तर प्रदेश के उत्पाद चैंपियनों संबंधी शीर्ष क्षेत्र	16
तालिका 3:	उत्तर प्रदेश के लिए अंडरअचीवर श्रेणियां	17

उत्तर प्रदेश से निर्यातः रुझान, अवसर और नीतिगत परिप्रेक्ष्य

परिचय

उत्तर प्रदेश (यूपी) कई दशकों से संस्कृतियों, धर्मों और व्यवसायों का संगम रहा है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो लगभग 95,000 वर्ग मील (246,000 वर्ग किमी) के क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत के कुल भूमि क्षेत्रफल के लगभग 7.3 प्रतिशत के बराबर है। यह राज्य उत्पादन (सकल राज्य घरेलू उत्पाद[1]) के मामले में पांचवें स्थान पर है, जो 2020-21 में देश के सकल घरेलू उत्पाद का 7.7 प्रतिशत रहा। हालांकि, 2021-22 के दौरान भारत के वस्तु निर्यातों में राज्य की हिस्सेदारी केवल 5.0 प्रतिशत रही, जो अन्य प्रमुख मैक्रोइकनॉमिक मानदंडों में राज्य की हिस्सेदारी की तुलना में काफी कम रही। यह उत्तर प्रदेश के लिए राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

साथ ही, देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस राज्य का योगदान 7.7 प्रतिशत है और यह राज्य उत्पादन (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के मामले में भी पांचवें स्थान पर है।

[1] स्थिर मूल्य पर, आधार वर्ष 2011–12, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

चार्ट 1: उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेट्रिक्स

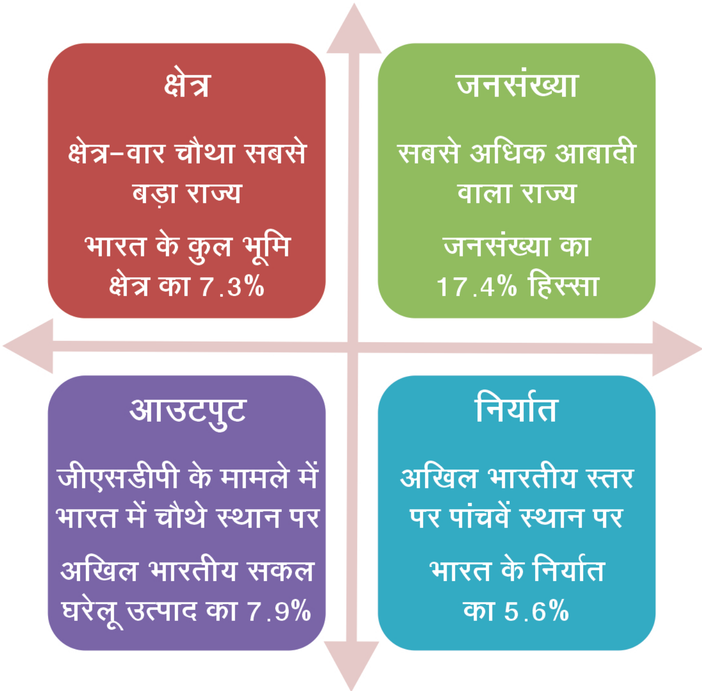

उत्तर प्रदेश बंदरगाह विहीन राज्य है जो पूर्व में बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर में उत्तराखंड राज्यों से घिरा हुआ है। नेपाल के साथ इस राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है। इसके साथ ही यह राज्य सड़कों, रेलवे और हवाई मार्ग के मामले में भी अच्छी कनेक्टिविटी के साथ देश के अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ है और देश के दोनों, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर इस राज्य से होकर गुजरते हुए दादरी के पास मिलते हैं। इसके अलावा, आने वाले समय में अन्य आगामी लॉजिस्टिक संवर्धन से भी राज्य में औद्योगिक विकास में तेजी आने की संभावना है।

प्रमुख आर्थिक गतिविधियां

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) किसी भी राज्य के आर्थिक विकास तथा अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों को मापने का महत्त्वपूर्ण संकेतक होता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर ही वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से उत्पन्न आय को मापा जाता है। उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर कोविड–19 से संबंधित व्यवधानों के चलते 2020–21 को छोड़कर, हाल की अवधि में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। केवल 2020-21 में (–) 5.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी (चार्ट 2)।

चार्ट 2: उत्तर प्रदेश के स्थिर मूल्यों (2011–12) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में रुझान

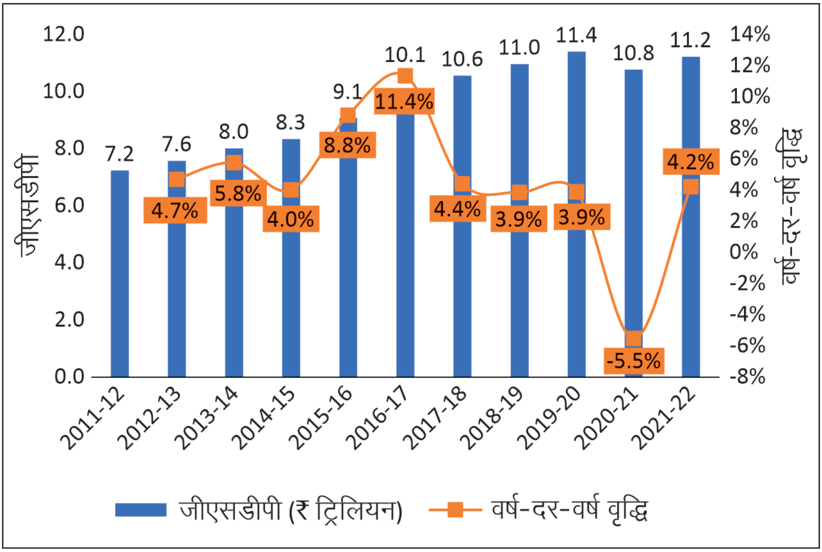

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एक्ज़िम बैंक रिसर्च

2021-22 में, उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में मूल मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र का योगदान 49.2 प्रतिशत का रहा। इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र (26.8 प्रतिशत) और प्राथमिक क्षेत्र (23.9 प्रतिशत) का स्थान रहा। राज्य के

जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र का घटता योगदान चिंता का कारण रहा है। 2016–17 में यह 30.6 प्रतिशत था, जो 2021-22 में घटकर 26.8 प्रतिशत (चार्ट 3) रह गया है। द्वितीयक क्षेत्र में, जीएसवीए में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 2016–17 के 18.2 प्रतिशत से 2021-22 में घटकर लगभग 14.2 प्रतिशत रह गई। यह द्वितीयक क्षेत्र, विशेष रूप से राज्य के विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादकता और स्पर्धात्मकता में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

चार्ट 3: क्षेत्र–वार जीएसवीए संरचना

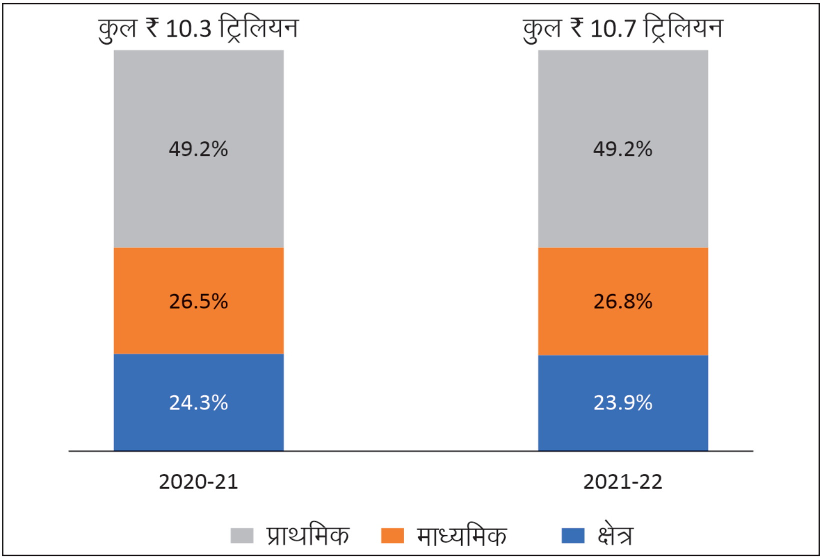

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एक्ज़िम बैंक रिसर्च

प्राथमिक क्षेत्र

उपजाऊ भूमि, उपयुक्त जलवायु और बारहमासी नदी प्रणाली से संपन्न, उत्तर प्रदेश लंबे समय से भारत का अन्न भंडार रहा है। राज्य में 28,500 किलोमीटर क्षेत्र में नदियों और नहरों का सबसे लंबा नेटवर्क है, जो कृषि क्षेत्र के लिए उपयोगी है।

उत्तर प्रदेश भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य में खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 में 58.1 मिलियन टन रहा, जो वर्ष के दौरान देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 18.7 प्रतिशत रहा। राज्य में उत्पादित प्रमुख खाद्यान्नों में चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, मटर और मसूर शामिल हैं। 2021-22[2] में 29.9 मिलियन टन के समग्र सब्जी उत्पादन के साथ, यह राज्य भारत में सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी रहा है।

उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख दूध उत्पादक राज्य के रूप में भी जाना जाता है। 2020-21 के दौरान, राज्य का दूध उत्पादन लगभग 31.4 मिलियन टन रहा, जो वर्ष के दौरान देश में उत्पादित कुल दूध का लगभग 14.9 प्रतिशत रहा। राष्ट्रीय डेयरी योजना उत्तर प्रदेश के आठ जिलों, मेरठ, अम्बेडकरनगर, लखनऊ, बिजनौर, गोंडा, फर्रुखाबाद, बाराबंकी और फैजाबाद में शुरू की गई है, जो राज्य के डेयरी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दे रही है।

औद्योगिक क्षेत्र

उत्तर प्रदेश अपने प्रमुख पारंपरिक उद्योगों के लिए लोकप्रिय है। इनमें हस्तशिल्प, चमड़े के सामान, कालीन, वस्त्र, चीनी, सूती धागे, जूट, वनस्पति तेल, कांच के बर्तन और चूड़ियां आदि शामिल हैं। कच्चे माल तक आसान पहुंच और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नई इकाइयों की स्थापना की विशाल क्षमता ने राज्य में चीनी निर्माण को बढ़ावा दिया है। नतीजतन, उत्तर प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है।

उत्तर प्रदेश में सुविकसित खनिज आधारित उद्योग भी है। राज्य चूना पत्थर, डोलोमाइट, कांच–रेत, संगमरमर, बॉक्साइट, गैर–प्लास्टिक फायरक्ले और यूरेनियम जैसे खनिज संसाधनों से संपन्न है, जो राज्य में खनिज आधारित उद्योगों के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करता है। चूना पत्थर और अन्य खनिजों जैसे कच्चे माल की उपलब्धता में समृद्धि के कारण, राज्य में 15 बड़े सीमेंट संयंत्र[3] हैं।

[2] राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, द्वितीय अग्रिम अनुमान 2019–20

[3] डीपीआईआईटी

पशुधन की बड़ी संख्या ने राज्य में चमड़ा उद्योग के फलने–फूलने के लिए अनुकूल परिवेश बनाया है। कानपुर और आगरा देश में चमड़े के सामान के केंद्र के रूप में उभरे हैं। चमड़ा क्षेत्र और अधिक विकसित होने वाला है, क्योंकि सरकार राज्य में एक मेगा चमड़ा क्लस्टर पार्क स्थापित कर रही है, जो लगभग ₹13,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करेगा। उत्तर प्रदेश देश में मांस का सबसे बड़ा निर्यातक भी है, जिसमें राज्य में 15 आधुनिक एकीकृत बूचड़खाने और 35 मांस प्रसंस्करण इकाइयां हैं।

कपड़ा उद्योग राज्य के लिए एक और आशाजनक क्षेत्र है। राज्य से कालीन और रेडीमेड वस्त्रों का उल्लेखनीय निर्यात होता है। हथकरघा और रेशम उत्पादन के मामले में राज्य देश में पांचवें स्थान पर है। राज्य में 2.58 लाख हथकरघा और 5.5 लाख पावरलूम बुनकर हैं। राज्य में गैर–लघु औद्योगिक क्षेत्र में 58 कताई मिलें और 74 कपड़ा मिलें भी हैं। नोएडा में एक परिधान निर्यात क्लस्टर भी स्थापित किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र को उल्लेखनीय निवेश मिलने की उम्मीद है।

अवसंरचना

उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादकों में से एक है। दिसंबर 2022 तक, उत्तर प्रदेश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 29,857 मेगावाट (एमडब्ल्यू)[4] थी। राज्य में अच्छे सड़क बुनियादी ढांचे के साथ–साथ दूरसंचार नेटवर्क भी सुदृढ़ हैं। राज्य का टेली घनत्व 66.9 प्रतिशत है और भारत में वायरलेस ग्राहकों में इसकी हिस्सेदारी 14.3 प्रतिशत है[5]। उत्तर प्रदेश में प्रति 1,000 वर्ग किमी में 40 किमी के रेलवे घनत्व के साथ देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भी है, जो भारत के रेल घनत्व से दोगुना है। कृषि, सीमेंट, उर्वरक, कोयला और विनिर्माण प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनके लिए रेलवे की सेवाएं ली जा रही हैं। विमानन अवसंरचना की बात करें तो उत्तर प्रदेश में छह घरेलू हवाई अड्डे हैं, जो आगरा, इलाहाबाद,

[4] सीईए

[5] टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन डेटा यथा 30 नवंबर, 2022 को, ट्राई

गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी में स्थित हैं। ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है।

सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से काफी आगे है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के 'बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान' (बीआरएपी) के तहत व्यवसाय सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) रैंकिंग के अनुसार, उत्तर प्रदेश 2019 में भारतीय राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे स्थान पर रहा, जो 2015 में 10 वें स्थान पर था।

सेवाएं

उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर, कैप्टिव बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित आईटी और आईटी आधारित उद्योगों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। यह सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए भी एक केंद्र बन गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कई प्रमुख कंपनियों के कार्यालय और अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) केंद्र हैं।

ऐतिहासिक शहर वाराणसी के अलावा आगरा का ताजमहल भी उत्तर प्रदेश में ही है, जिसके कारण यह राज्य भारत में पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक बना हुआ है। 2021 में, उत्तर प्रदेश में भारत से कुल 16.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ घरेलू पर्यटकों की सबसे अधिक संख्या रही। उत्तर प्रदेश 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला (एफटीवी) तीसरा सबसे बड़ा राज्य भी था, जिसकी देश के कुल एफटीवी में 4.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही[6]।

उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नौ और सर्किट शुरू करने की योजना बना रहा है[7]। विश्व बैंक ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 'प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना' के तहत पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 40 मिलियन यूएस डॉलर

[6] भारत पर्यटन सांख्यिकी एक नज़र 2020, पर्यटन मंत्रालय

[7] इसमें महाभारत सर्किट, कृष्ण सर्किट, जैन सर्किट, सूफी सर्किट, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट, कांवड़ सर्किट, क्राफ्ट सर्किट, व्यंजन सर्किट और संस्कृति सर्किट शामिल हैं।

(लगभग ₹260 करोड़) की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह पंचवर्षीय कार्यक्रम लगभग 57.14 मिलियन यूएस डॉलर का है, जिसमें से 40 मिलियन यूएस डॉलर का वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा, और शेष राशि राज्य बजट से वित्तपोषित की जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित पर्यटन स्थलों पर स्थानीय समुदायों के लिए पर्यटन से संबंधित लाभों को बढ़ाना है।

निर्यात परिदृश्य

देश के निर्यातों में उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय योगदान रहता है। इसकी वजह है, विविधतापूर्ण उत्पादन और बेहतर मूल्यवर्धन नेटवर्क तथा संसाधन क्षमताओं का सदुपयोग। 2021-22 के दौरान, निर्यात मूल्य की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में पांचवें स्थान पर रहा। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य से वस्तु निर्यात 21.0 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जो 2015–16 में 12.4 बिलियन यूएस डॉलर का था (चार्ट 4)। वित्तीय वर्ष 2016 से वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान राज्य से निर्यात में 9.7 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर दर्ज की गई, जो वस्तु निर्यातों के 9.4 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत से बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश भारत के वस्तु निर्यातों में अपनी हिस्सेदारी

चार्ट 4: उत्तर प्रदेश से वस्तु निर्यातों में रुझान

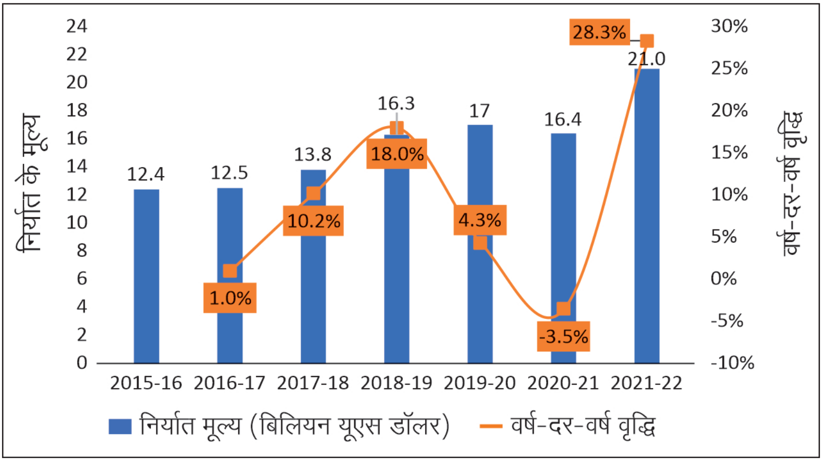

स्रोत: डीजीसीआईएस, एक्ज़िम बैंक रिसर्च

2015–16 में 4.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 2020–21 में 5.0 प्रतिशत करने में सक्षम रहा है। राज्य से निर्यात में इस वृद्धि का श्रेय आंशिक रूप से विनिर्माण और निर्यात के लिए अनुकूल नीतिगत परिवेश को दिया जा सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। 2020–21 में उत्तर प्रदेश के वस्तु निर्यात में इसकी लगभग 20.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (9.9 प्रतिशत की हिस्सेदारी), जर्मनी (5.1 प्रतिशत), नेपाल (6.2 प्रतिशत), ब्रिटेन (5.6 प्रतिशत), और हांगकांग (2.8 प्रतिशत) (चार्ट 5) का स्थान रहा। राज्य से लगभग 19.2 प्रतिशत वस्तु निर्यात न्हावा शेवा के माध्यम से किया गया। राज्य से वस्तु निर्यात के लिए अन्य प्रमुख पोर्ट में सीजीएमएल दादरी (18.4 प्रतिशत), दिल्ली हवाई अड्डा (9.1 प्रतिशत), सीएफएस अल्बाट्रॉस/आईसीडी दादरी (7.5 प्रतिशत) और आईसीडी नोएडा–दादरी (5.7 प्रतिशत) शामिल हैं। राज्य से अधिकांश वस्तु निर्यात या तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के पोर्ट के माध्यम से किया जाता है। राज्य के पूर्वी भाग में भी व्यापार अनुकूल अवसंरचना के निर्माण और अधिक क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।

चार्ट 5: उत्तर प्रदेश से वस्तु निर्यातों के लिए शीर्ष गंतव्य (2021–22)

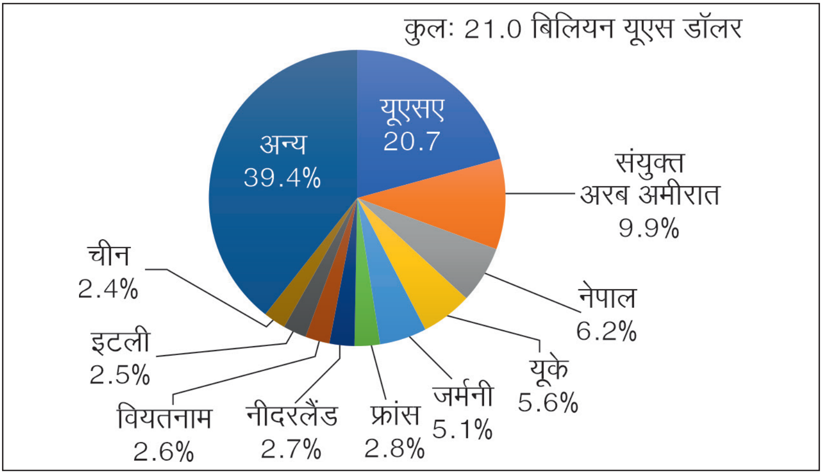

स्रोतः डीजीसीआईएस, एक्ज़िम बैंक रिसर्च

चार्ट 6: उत्तर प्रदेश से निर्यातित शीर्ष उत्पाद (2021–22)

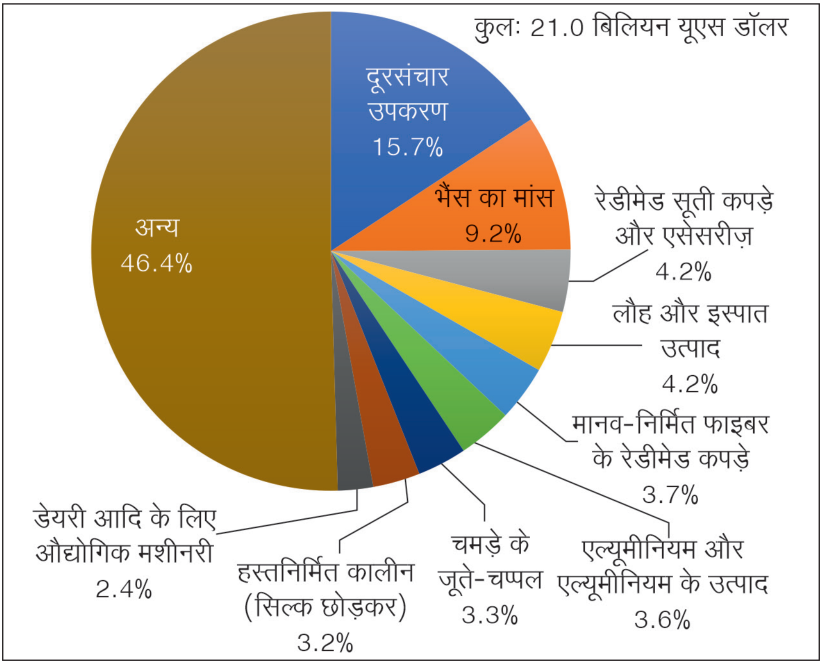

स्रोतः डीजीसीआईएस, एक्ज़िम बैंक रिसर्च

राज्य से निर्यात किए जाने वाले कुछ प्रमुख उत्पादों में अन्य के साथ–साथ, दूरसंचार उपकरण (वित्तीय वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के कुल वस्तु निर्यात में 15.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी), भैंस का मांस (9.2 प्रतिशत), लौह और इस्पात के उत्पाद (4.2 प्रतिशत), एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम के उत्पाद (3.6 प्रतिशत), रेडीमेड सूती वस्त्र (3.7 प्रतिशत), और मानव निर्मित फाइबर के रेडीमेड परिधान (3.7 प्रतिशत) शामिल हैं। (चार्ट 6)। उत्तर प्रदेश देश से विभिन्न निर्यात श्रेणियों में सबसे बड़े निर्यातक राज्यों में से एक है। 2021–22 के दौरान, सैडलरी के निर्यातों में लगभग 90 प्रतिशत योगदान उत्तर प्रदेश का ही रहा।

2021–22 के दौरान, भैंस के मांस, रेशम के कालीन, पशु केसिंग और तैयार चमड़े जैसी कई अन्य श्रेणियों में, उत्तर प्रदेश से वस्तु निर्यात भारत से वस्तु निर्यात का लगभग आधे से अधिक रहा। खेल वस्तुओं का भी उत्तर प्रदेश से उल्लेखनीय

निर्यात होता है। भारत से इन उत्पादों के कुल निर्यात का लगभग एक तिहाई हिस्सा उत्तर प्रदेश से ही निर्यात होता है (तालिका 1)।

तालिका 1: भारत के निर्यात में उच्चतम हिस्सेदारी वाले उत्पाद (2021–22)

उत्पाद	निर्यात मूल्य (मिलियन यूएस डॉलर में)	भारत के निर्यात में हिस्सेदारी
सैडलरी और हार्नेस	247.7	90%
भैंस का मास	1928.0	58%
रेशम के कालीन	19.9	55%
पशु केसिंग	33.8	53%
तैयार चमड़ा	226.2	50%
प्रसंस्कृत मांस	0.7	47%
दूरसंचार उपकरण	3309.0	45%
प्राकृतिक रेशम के धागे, फैब्रिक्स, मेड अप	35.1	44%
अन्य अलौह धातु और उत्पाद	320.8	40%
भेड़/ बकरी के मांस	23.2	39%
हस्त निर्मित कालीन (सिल्क छोड़कर)	668.9	38%
खेल वस्तुएं	135.4	36%
चमड़े के जूते–चप्पल	699.6	34%
चमड़े के जूते–चप्पल के घटक	66.9	27%
प्लाईवुड और उससे संबंधित उत्पाद	413.8	25%
ग्लास एवं ग्लासवेयर	262.3	24%
मानव–निर्मित फाइबर से बने रेडिमेड कपड़े	788.4	24%
पुस्तकें, प्रकाशन और प्रिंटिंग	76.0	21%
रबड़ /कैनवास अदि के जूते-चप्पल	44.4	21%
हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कार्पेट को छोड़कर)	395.9	19%

स्रोतः डीजीसीआईएस, एक्ज़िम बैंक रिसर्च

अप्रयुक्त निर्यात संभाव्यताएं और प्रमुख फोकस क्षेत्र

आईटीसी निर्यात संभाव्यता मानचित्र के आंकड़ों पर आधारित अनुमानों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में वस्तु निर्यातों में लगभग 12.0 बिलियन यूएस डॉलर की अप्रयुक्त निर्यात क्षमता है। इस अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने से उत्तर प्रदेश से वस्तु निर्यात लगभग 33 बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ सकता है।

निर्यात संभाव्यता को भुनाने के लिए, निर्यात रणनीति उन वस्तुओं पर केंद्रित होनी चाहिए जिनमें आपूर्ति और मांग पक्ष दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विकास की अधिकतम क्षमता हो। इसमें उन उत्पादों का बारीक विश्लेषण शामिल होगा, जिनमें राज्य को तुलनात्मक लाभ है और उन उत्पादों की वैश्विक आयात मांग है। इस विश्लेषण के लिए एक आवश्यक पहला कदम तुलनात्मक लाभ का परिमाणीकरण (मापना) होगा, जिससे ऐसे उत्पादों को चिह्नित करने में मदद मिलेगी, जिनका राज्य से अच्छा निर्यात रहा है और सफलता भले सीमित रही है, किन्तु जिनमें निर्यात के उल्लेखनीय अवसर हैं।

तुलनात्मक लाभ की मात्रा का परिमाणीकरण करने के लिए, प्रकट तुलनात्मक लाभ (आरसीए) की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। आरसीए सूचकांकों का उपयोग निर्यात श्रेणियों को चिह्नित करने के लिए किया जाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था को विश्व व्यापार परिदृश्य के साथ देश के व्यापार परिदृश्य की तुलना के माध्यम से तुलनात्मक लाभ होता है। प्रकट तुलनात्मक लाभ की अवधारणा में अंतर्निहित मूल धारणा यह है कि व्यापार प्रोफाइल सापेक्ष लागतों के साथ–साथ गैर–मूल्य पहलुओं के संदर्भ में अंतर–देशीय अंतर को दर्शाती है। बालासा (1965) के माप के अनुसार, देश i, कमोडिटी j के लिए आरसीए सूचकांक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है–

$$RCA_{ij} = \frac{(X_{ji}/X_i) / (X_{wj}/X_w)}{(X_{ji}/X_i) / (X_{wj}/X_w)}$$

जहां,

X_{ji}: देश i से वस्तु का निर्यात

XI: देश i से कुल निर्यात

X_{wj}: दुनिया से कमोडिटी j का कुल निर्यात

X_w: दुनिया से कुल निर्यात

आरसीए सूचकांक 0 से अनंत तक होता है, जिसमें 1 ब्रेक–ईवन बिंदु के रूप में होता है। अर्थात 1 से कम के आरसीए मूल्य का मतलब है कि उत्पाद का कोई निर्यात तुलनात्मक लाभ नहीं है, जबकि 1 से ऊपर का मूल्य इंगित करता है कि उत्पाद का तुलनात्मक लाभ है।

सामान्यीकृत प्रकट तुलनात्मक लाभ (एनआरसीए) सूचकांक, अन्य वैकल्पिक आरसीए सूचकांकों की तुलना में तुलनात्मक लाभ की सीमा को अधिक सटीक और लगातार प्रकट करने में सक्षम है। एनआरसीए को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया जा सकता है –

$$NRCAij = \frac{(RCA_{ij} -1)}{(RCA_{ij} +1)}$$

सकारात्मक एनआरसीए मूल्य इंगित करता है कि उत्तर प्रदेश को उस उत्पाद के निर्यात में तुलनात्मक लाभ है, जबकि नकारात्मक एनआरसीए मूल्य उस उत्पाद के निर्यात में उत्तर प्रदेश के तुलनात्मक लाभ की कमी को इंगित करता है। इसमें केवल उन उत्पादों पर विचार किया गया है जिनका पर्याप्त वैश्विक आयात है और उत्तर प्रदेश से जिनका निर्यात भी होता है।

जैसा कि एनआरसीए में परिलक्षित होता है, उत्तर प्रदेश की निर्यात स्पर्धात्मकता को 2017 से 2021 की अवधि के दौरान उत्पादों की वैश्विक मांग के साथ मैप किया गया है। इस मानचित्रण के आधार पर, उत्पादों की चार श्रेणियों को चिह्नित किया गया है:

- **उत्पाद चैंपियन – प्रतिस्पर्धी निर्यात (एनआरसीए > 0)**; बढ़ती आयात मांग (उत्पाद आयात एएजीआर > 0): ये अधिकतम क्षमता वाले उत्पाद हैं, क्योंकि 2017 से 2021 के दौरान इन उत्पादों की वैश्विक मांग में अच्छी वृद्धि हुई है, और इन उत्पादों में उत्तर प्रदेश निर्यात प्रतिस्पर्धी है। इन्हें लघु से मध्यम अवधि में निर्यात वृद्धि हासिल करने के लिए लक्षित किया जा सकता है। इन्हें उत्पाद चैंपियन कहा जा सकता है।

- **अंडरअचीवर्स – निर्यात प्रतिस्पर्धी नहीं हैं (एनआरसीए < 0)**; बढ़ती आयात मांग (उत्पाद आयात एएजीआर > 0): उत्तर प्रदेश को इन उत्पादों में तुलनात्मक लाभ प्राप्त नहीं है, लेकिन इन उत्पादों की आयात मांग ने विचाराधीन अवधि में सकारात्मक वृद्धि दिखाई है। राज्य द्वारा मध्यम से लंबी अवधि में इन उत्पादों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं।

- **गिरावट वाले क्षेत्र – निर्यात प्रतिस्पर्धी नहीं हैं (एनआरसीए < 0)**; कमजोर आयात मांग (उत्पाद आयात एएजीआर < 0): उत्तर प्रदेश को इन उत्पादों में तुलनात्मक लाभ प्राप्त नहीं है, और इस क्षेत्र ने विचाराधीन अवधि के दौरान नकारात्मक वैश्विक आयात वृद्धि भी दर्ज की है। इनमें विविधीकरण की आवश्यकता है।

- **प्रतिकूल परिस्थितियों में अचीवर– प्रतिस्पर्धी निर्यात (एनआरसीए > 0)**; कमजोर आयात मांग (उत्पाद आयात एएजीआर < 0): उत्तर प्रदेश में इन उत्पादों में प्रतिस्पर्धा है, लेकिन इन उत्पादों के लिए वैश्विक आयात मांग नकारात्मक रही है। इन क्षेत्रों में विविधता लाने की आवश्यकता है।

विश्लेषण से पता चलता है कि एचएस–6 अंक स्तर पर लगभग 92 उत्पाद हैं, जिन्हें उत्पाद चैंपियन कहा जा सकता है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स (विशेष रूप से मोबाइल फोन) जैसे उत्पाद शामिल हैं; मांस उत्पाद; कीमती धातुओं की वस्तुएं; लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम, तांबे की वस्तुएं; चावल जैसे अनाज; पुदीना सत्त; वस्त्र; जूते; चमड़े के उत्पाद; मोटर वाहन जैसे मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर, साथ ही

चुनिंदा ऑटो–घटक जैसे उत्पाद शामिल हैं। इन 92 उत्पादों का निर्यात 2021 में उत्तर प्रदेश के कुल निर्यात का लगभग 60.15 प्रतिशत रहा (चार्ट 7)। चूंकि ये उत्पाद सुलभ हैं, इसलिए इनमें उत्तर प्रदेश से निर्यात बढ़ाने की अधिकतम क्षमता है। इन उत्पादों के क्षेत्रवार वर्गीकरण से पता चलता है कि वस्त्र और संबद्ध उत्पादों में उत्पाद चैंपियनों की सबसे बड़ी संख्या (6 अंकों के स्तर पर 16 एचएस कोड) है, जबकि मूल्य के संदर्भ में, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण उत्पाद चैंपियन क्षेत्र हैं (तालिका 2)।

चार्ट 7: उत्तर प्रदेश से निर्यात के लिए उत्पादों का चिह्नीकरण (2021)

उत्पाद चैंपियन (92 उत्पाद)	**प्रतिकूल परिस्थितियों में अचीवर (49 उत्पाद)**
यूपी का निर्यातः 12.1 बिलियन यूएस डॉलर यूपी के निर्यात में 60.15% की हिस्सेदारी विश्व आयातः 1369.4 बिलियन यूएस डॉलर	यूपी का निर्यातः 3.2 बिलियन यूएस डॉलर यूपी के निर्यात में 15.81% की हिस्सेदारी विश्व आयातः 400.2 बिलियन यूएस डॉलर
कुल उत्पादः 155	
अंडर अचीवर (11 उत्पाद)	**गिरावट वाले क्षेत्र (3 उत्पाद)**
यूपी का निर्यातः 453.0 मिलियन यूएस डॉलर यूपी के निर्यात में 2.26% की हिस्सेदारी विश्व आयातः 1934.2 बिलियन यूएस डॉलर	यूपी का निर्यातः 274.1 मिलियन यूएस डॉलर यूपी के निर्यात में 1.37% की हिस्सेदारी विश्व आयातः 771.0 बिलियन यूएस डॉलर

स्रोतः डीजीसीआईएस, आईटीसी ट्रेडमैप, एक्ज़िम बैंक रिसर्च

तालिका 2: उत्तर प्रदेश के उत्पाद चैंपियनों संबंधी शीर्ष क्षेत्र

उत्पाद	2019 में उत्तर प्रदेश से निर्यात (मूल्य मिलियन यूएस डॉलर में)	6-डिजिट एच एस कोड
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स	3,065.3	3
पशु; पशु उत्पाद	1,968.6	5
धातु और धातु की वस्तुएं	1,725.1	16
कपड़ा और संबंधित क्षेत्र	838.1	13
कृषि उत्पाद	638.3	4
फर्नीचर और संबंधित वस्तुएं	478.3	6
रसायन और संबंधित उत्पाद	451.5	7
परिवहन उपकरण	434.1	5
प्रसंस्कृत खाद्य	426.1	5
चमड़ा और संबंधित उत्पाद	363.2	6
रत्न और आभूषण	202.1	1
अन्य	1,466.8	21
कुल योग	**12,057.5**	**92**

स्रोत: डीजीसीआईएस, आईटीसी ट्रेडमैप, एक्ज़िम बैंक रिसर्च

मध्यम से लंबी अवधि में, राज्य को अंडरअचीवर खंड में क्षमताओं के विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जहां राज्य को वर्तमान में तुलनात्मक लाभ प्राप्त नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में वैश्विक आयात मांग मजबूत रही है। यद्यपि उत्तर प्रदेश के निर्यातकों की इन क्षेत्रों में उपस्थिति है, जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मासूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक, इलेक्ट्रिकल मशीनरी के पुर्जे, प्लास्टिक के सामान आदि शामिल हैं (तालिका 3), इन उत्पादों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है।

तालिका 3: उत्तर प्रदेश के लिए अंडरअचीवर श्रेणियां

एच एस कोड	एच एस विवरण	2021 में उत्तर प्रदेश से निर्यात (यूएस मिलियन डॉलर)
851770	सेलुलर फोन के पुर्जे	112.6
300490	चिकित्सीय या रोगनिरोधी प्रयोजनों के लिए मिश्रित या अमिश्रित उत्पादों की दवाएं	90.4
854232	मेमोरी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट	36.2
854239	इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट (प्रोसेसर, कंट्रोलर, मेमरीज़ और एम्प्लिफायर को छोड़कर)	35.9
392690	प्लास्टिक की वस्तुएं	32.8
853890	अकेले इस्तेमाल या मुख्य रूप से विद्युत उपकरणों के साथ इस्तेमाल के पुर्जे	32.6
760612	एल्यूमीनियम अलॉय की प्लेटें, चादरें और स्ट्रिप्स	26.0
854231	प्रोसेसर एवं कंट्रोलर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट	24.3
852990	अकेले इस्तेमाल या मुख्य रूप से फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल के लिए उपयुक्त पुर्जे	21.4
901839	चिकित्सा विज्ञान में उपयोग की जाने वाली सुई, कैथेटर, कैनुला	20.5
611020	सूती जर्सी, पुलओवर, कार्डिगन, वेस्टकोट और इसी तरह के उत्पाद	20.2
कुल		**453.0**

स्रोत : डीजीसीआईएस, आईटीसी ट्रेडमैप, एक्ज़िम बैंक रिसर्च

उत्तर प्रदेश की निर्यात तत्परता का तुलनात्मक मूल्यांकन

नीति आयोग का निर्यात तत्परता सूचकांक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात निष्पादन को उनके समकक्षों के मुकाबले बेंचमार्क करता है और राज्य स्तर पर निर्यात के लिए बेहतर नीतिगत तंत्र विकसित करने के लिए संभावित चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण करता है। सूचकांक में, उत्तर प्रदेश को बंदरगाह विहीन राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश इस श्रेणी में राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से पीछे है। राज्य ईपीआई के कई स्तंभों, जैसे निर्यात प्रणाली और निर्यात निष्पादन पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य से भी पीछे है, तथापि निर्यात नीति के संदर्भ में, यह राज्य सबसे अच्छे निष्पादन वाले राज्य के अपेक्षाकृत करीब है (चार्ट 8)।

चार्ट 8: बंदरगाह विहीन राज्यों और सर्वश्रेष्ठ निष्पादन वाले राज्यों के साथ ईपीआई पर उत्तर प्रदेश की तुलना

बंदरगाह विहीन राज्य	ईपीआई स्कोर
हरियाणा	53.20
उत्तर प्रदेश	51.09
मध्य प्रदेश	51.03
पंजाब	50.99
तेलंगना	47.92
राजस्थान	47.13
असम	41.57
झारखंड	38.16
छत्तीसगढ़	36.96
बिहार	32.06

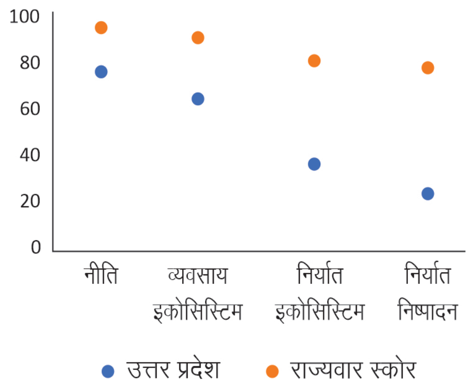

स्रोतः ईपीआई 2021, नीति आयोग

उत्तर प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए चुनिंदा रणनीति

उत्तर प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी रणनीति में समग्र दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इस रणनीति में राज्य में निर्यातकों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। साथ ही, नए निर्यात अवसरों का दोहन करने में राज्य की तैयारियों में सुधार करने और विभिन्न स्तरों पर रणनीति बनाने की जरूरत है।

बाजार और उत्पाद विविधीकरण

राज्य को उच्च मूल्य वर्धित वस्तुओं में अपने निर्यात बास्केट में विविधता लाने की आवश्यकता है। निर्यात बास्केट का विस्तार करने के तरीकों में से एक मूल्य संवर्धन के आधार पर उत्पाद विविधीकरण करना है। निर्यात विविधीकरण के लिए दो तरीके हैं– क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) और ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) विविधीकरण। क्षैतिज विविधीकरण एक ही क्षेत्र में उसी क्षेत्र के भीतर मौजूदा निर्यात बास्केट में नए उत्पादों को जोड़कर होता है और ऊर्ध्वाधर विविधीकरण में प्राथमिक से द्वितीयक से तृतीयक क्षेत्र में बदलाव पर जोर दिया जाता है। ऊर्ध्वाधर विविधीकरण में मूल्य वर्धित सेवाओं, प्रसंस्करण, मार्केटिंग या अन्य सेवाओं के माध्यम से मौजूदा उत्पादों के और अधिक उपयोग पर बल दिया जाता है।

उदाहरण के लिए, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में, प्रसंस्करण गतिविधियों में ऊर्ध्वाधर विविधीकरण की दिशा में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। एक उदाहरण राज्य के पशुधन से संबंधित क्षेत्र का है। पशुधन से संबंधित उत्पाद राज्य के लिए प्रमुख निर्यात वस्तु हैं, लेकिन प्रसंस्कृत पशुधन उत्पादों का राज्य का निर्यात वर्तमान में सीमित है। वर्तमान में, मांस राज्य से निर्यात की एक उल्लेखनीय वस्तु है, लेकिन प्रसंस्कृत मांस का निर्यात सीमित है। उच्च मूल्य वर्धित मांस उत्पादों की ओर निर्यात के विविधीकरण से अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर मार्जिन मिल सकता है।

मसाला ओलियोरेसिन के रूप में प्रसंस्कृत मसालों का निर्यात करना राज्य के लिए एक और उभरता हुआ अवसर है। ओलियोरेसिन में सक्रिय घटक अधिक होते हैं, इसलिए छोटी खुराकों में उनका उपयोग किया जाता है। साथ ही स्वाद में

मानकीकरण और स्थिरता के लिए भी ये अग्रणी हैं। ये ओलियोरेसिन पेय पदार्थ, कन्फेक्शनरी, मीट कैनिंग, सॉस, फार्मासूटिकल्स, मसाला आदि जैसे उद्योगों में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, मिर्च ओलियोरेसिन का उपयोग उनके एनाल्जेसिक, एंटीऑक्सिडेंट, एंटी–कैंसर और एंटी–सूजन गुणों के कारण दवा अनुप्रयोगों में तेजी से किया जा रहा है, जबकि काली मिर्च ओलियोरेसिन की मांग भी उनके एंटीऑक्सिडेंट और रोगाणुरोधी विशेषताओं के कारण बढ़ रही है। इसी तरह, हल्दी ओलियोरेसिन स्किन केयर उद्योग में लोकप्रिय हो रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देश जैसे यूके, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन और ऑस्ट्रिया दुनिया में मसाला ओलियोरेसिन के शीर्ष आयातकों में शामिल हैं[8]।

विनिर्माण क्षेत्र में, वस्त्र क्षेत्र निर्यात के लिए उल्लेखनीय अवसर प्रदान करता है। हालांकि राज्य सरकार ने कपड़ा और संबद्ध उद्योगों के आधुनिकीकरण और मेगा क्लस्टर के माध्यम से इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की दिशा में पहले ही कदम उठाए हैं, तथापि घरेलू वस्त्र और तकनीकी वस्त्र जैसे क्षेत्रों में वस्त्र मूल्य श्रृंखला में विविधता लाने की आवश्यकता है।

हाल ही में कोविड–19 संकट के बाद भारतीय दवा क्षेत्र के लिए 7.3 बिलियन यूएस डॉलर के अवसर खुले हैं। उत्तर प्रदेश इस अवसर का उपयोग थोक दवाओं और फॉर्मूलेशन की वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए कर सकता है। इस संदर्भ में, राज्य केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों जैसे "उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना" का लाभ उठाकर थोक दवाओं और फार्मूलेशनों के उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकता है। यह योजना पात्र निर्माताओं को 6 साल (वित्तीय वर्ष 2020–26) की अवधि के लिए उनकी वृद्धिशील बिक्री पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर 53 महत्त्वपूर्ण दवा फॉर्मूलेशनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। थोक दवाएं विशेष रूप से राज्य के लिए एक फोकस क्षेत्र होना चाहिए क्योंकि ये प्रमुख इनपुट हैं, और हाल की अवधि में इन उत्पादों के लिए चीन पर आयात निर्भरता बढ़ गई है।

कोविड–19 महामारी के दौरान किए गए उल्लेख के अनुसार, आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान का दवा कंपनियों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, राज्य को

[8] आईएसआई इमर्जिंग मार्कर– ग्रैंड व्यू रिसर्च

अधिक थोक दवा इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में थोक दवा पार्क भी स्थापित किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में उभरते उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में से एक हैं। राज्य को इन उच्च प्रौद्योगिकी गहन क्षेत्रों में उत्पादन और निर्यात क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कृषि उत्पादों और संसाधन–गहन विनिर्माण की तुलना में कम अस्थिर हैं, जो कमोडिटी की कीमतों में उतार–चढ़ाव से ग्रस्त हैं। ये क्षेत्र राज्य में उच्च कौशल वाले रोजगार भी पैदा करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इसमें उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना भी शामिल है। इन क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य द्वारा इन योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है और संभावित निवेशक तलाशे जा सकते हैं।

राज्य लिथियम आयन, स्टैटिक कन्वर्टर्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, चिकित्सा उपकरणों तथा उपकरणों के उत्पादन और निर्यात को भी प्रोत्साहित कर सकता है। ये बड़े और बढ़ते वैश्विक आयात वाले उत्पाद हैं। इन उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में से कुछ में उत्पादन और निर्यात के लिए, राज्य को निर्यात–उन्मुख विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि घरेलू क्षमताएं सीमित हैं। "मेक इन यूपी" कार्यक्रम के तहत इन क्षेत्रों को अधिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

कोविड–19 महामारी ने सभी उद्योग क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग के पारंपरिक रूप की नींव को हिला दिया है, और कंपनियां तेजी से री–शोरिंग और क्षेत्रीयकरण का विकल्प चुन रही हैं। रीशोरिंग से देश/क्षेत्र के भीतर मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों में मूल्य वर्धित गतिविधियों के स्थानीयकरण पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। क्षेत्रीयकरण की प्रवृत्ति से अधिक मजबूत और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला बनाने के प्रयास में क्षेत्रीय बाजार–मांग वाले निवेशों में अधिक निवेश होगा। पारंपरिक मॉडल को एक ऐसे मॉडल द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने की उम्मीद है जहां मांग के बिंदु के करीब

क्षेत्रीय रसद केंद्र प्रचलित हैं, जिससे निर्माता स्थानीय घटक और उप–प्रणाली आपूर्तिकर्ताओं और उत्पाद इंटीग्रेटर्स से प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य एक बड़ा बाजार प्रदान करता है, इसलिए बढ़ते बाजार का प्रभावी ढंग से दोहन करने के लिए राज्य में उत्पादन और वितरण मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण में अधिक विदेशी कंपनियों से निवेश किए जाने की उम्मीद है। ये उत्पादन आधार अन्य देशों में मांग को भी पूरा करेंगे, जिससे राज्य से निर्यात में वृद्धि होगी। इन घटनाक्रमों के आलोक में, "मेक इन यूपी" कार्यक्रम को "उत्तर प्रदेश में असेंबल करें" की रणनीति को शामिल किया जा सकता है। यह भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" पहल में "दुनिया के लिए भारत में असेंबलिंग" के अनुरूप भारत के आर्थिक सर्वेक्षण, 2019–20 में उल्लिखित परिप्रेक्ष्य के मुताबिक होगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार, "मेक इन इंडिया" पहल में "एसेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड" को एकीकृत करने से भारत को दुनिया में नेटवर्क उत्पादों के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी 2025 तक लगभग 3.5 प्रतिशत और 2030 तक 6 प्रतिशत तक बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश के निर्यात के लिए बाजारों के विविधीकरण की भी आवश्यकता है। उत्पाद चैंपियन वस्तुओं के उत्तर प्रदेश के निर्यात के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि ये निर्यात कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित हैं (अनुलग्नक 1)। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में निर्माताओं द्वारा निर्यात किए जाने वाले कई उत्पादों के लिए शीर्ष गंतव्य इन उत्पादों के लिए प्रमुख आयात बाजार नहीं हैं। उदाहरण के लिए, भैंस के जमे हुए, हड्डी रहित मांस (एचएस 020230) के मामले में, मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया उत्तर प्रदेश से इन उत्पादों के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्यों में शामिल हैं, लेकिन ये इस उत्पाद के शीर्ष 5 वैश्विक आयातकों में शामिल नहीं हैं। इस बीच हाफ–मिल्ड या पूरी तरह से मिल्ड चावल के मामले में, चाहे पॉलिश किए हुए (एचएस 100630), अमेरिका उत्तर प्रदेश से निर्यात के लिए शीर्ष 5 गंतव्यों में शामिल नहीं है। किन्तु अमेरिका इस उत्पाद के सबसे बड़े आयातकों में से एक है।

कुछ उत्पादों के निर्यात में भी उल्लेखनीय बाजार संकेंद्रण है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश से चांदी (एचएस 711319) के अलावा कीमती धातु के आभूषणों के

एक तिहाई से अधिक निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को किए जाते हैं, हालांकि विश्व आयात में संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा अपेक्षाकृत कम 11.8 प्रतिशत है। स्विट्जरलैंड, इन उत्पादों के लिए दूसरा सबसे बड़ा आयात बाजार है, किन्तु उत्तर प्रदेश से इन उत्पादों के निर्यात के लिए शीर्ष 5 गंतव्यों में शामिल नहीं है। जाहिर है, उत्पादों के लिए शीर्ष आयात बाजारों को लक्षित करने और निर्यात बास्केट में विविधता लाने की आवश्यकता है।

रक्षा निर्यात को बढ़ावा

हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए घरेलू रक्षा उद्योग में निवेश और क्षमता विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत इस क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ किया गया है, जिसमें भारत में रक्षा उत्पादन के लिए निवेश परिवेश में सुधार, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और रक्षा खरीद के लिए बाहरी निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इन उपायों के साथ, भारत सरकार को उम्मीद है कि भारत में रक्षा उत्पादन उद्योग का कारोबार 2025 तक ₹1,75,000 करोड़ (25 बिलियन यूएस डॉलर) तक पहुंच जाएगा, और निर्यात ₹35,000 करोड़ (5 बिलियन यूएस डॉलर) के स्तर तक पहुंच जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षा विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश रक्षा और एयरोस्पेस इकाइयां और रोजगार संवर्धन नीति 2018 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य पांच साल की अवधि में ₹50,000 करोड़ (7.46 बिलियन यूएस डॉलर) का निवेश उत्पन्न करना और 0.25 मिलियन नौकरियां पैदा करना है। फरवरी 2020 में, राज्य ने डिफेंस एक्सपो–2020 का भी आयोजन किया। इस दौरान राज्य को निवेश के लिए ₹5 लाख करोड़ (70.93 बिलियन यूएस डॉलर) के प्रस्ताव मिले। झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट और अलीगढ़ शहरों के साथ राज्य में एक रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर भी स्थापित किया गया है। रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर से रक्षा और एयरोस्पेस से संबंधित वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन

मिलने की उम्मीद है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी और अन्य देशों को इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अन्य विनिर्मित वस्तुओं के विपरीत, रक्षा निर्यात का वित्तपोषण और सुगमीकरण अक्सर मध्यम से दीर्घकालिक होता है। निर्यात ऋण एजेंसियों (ईसीए) की संस्थागत संरचना उन्हें ऐसी मध्यम से दीर्घकालिक निर्यात ऋण आवश्यकताओं को सुगम बनाने और वित्तपोषित करने में सक्षम बनाती है। कई निर्यात ऋण एजेंसियों में घरेलू रक्षा उद्योग के विकास में सहयोग के लिए अलग से कार्यक्रम हैं, जो अक्सर उनके वाणिज्यिक खातों से अलग होते हैं। अन्य ईसीए की तरह, इंडिया एक्ज़िम बैंक भी अपने ऋण–व्यवस्था और एनईआईए के अंतर्गत क्रेता ऋण जैसे विभिन्न प्रमुख वित्तपोषण कार्यक्रमों के जरिए भारत से जहाजों और वाहनों सहित रक्षा संबंधी उत्पादों और उपकरणों के निर्यात और रक्षा संबंधी सेवाओं को सहयोग कर रहा है। विदेशी बाजारों में अवसरों और एक्ज़िम बैंक से मध्यम से दीर्घकालिक वित्तपोषण विकल्पों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार बैंक के सहयोग से रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर में रक्षा निर्यातकों के लिए निर्यात अवसरों और वित्तपोषण विकल्पों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। राज्य सरकार रक्षा वस्तु क्षेत्र में फर्मों को क्रेडिट–लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक रक्षा विकास कोष स्थापित करने पर भी विचार कर सकती है। इससे राज्य में रक्षा वस्तुओं के लिए निवेश परिवेश में और सुधार हो सकता है और रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की सफलता सुनिश्चित हो सकती है। उल्लेखनीय है कि इस तरह का दृष्टिकोण चीन और ब्राजील जैसे देशों द्वारा भी अपनाया गया है।

पूंजीगत वस्तुओं के विकास को बढ़ावा

पूंजीगत वस्तु क्षेत्र औद्योगिक विकास के संचालकों में से एक है। डेयरी के लिए औद्योगिक मशीनरी, मशीन टूल्स, एसी और प्रशीतन मशीनरी, इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण जैसे खंड राज्य में विनिर्माण क्षेत्र के आगे के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण होंगे। नवोद्यमों (स्टार्ट–अप) को 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डिजिटलीकरण आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए, सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी

(पीपीपी) मोड में राज्य भर में कई इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना पर विचार कर सकती है, ताकि उच्च तकनीक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन और / या विकास में लगे नवोद्यमों का सहयोग किया जा सके। राज्य सरकार और उद्योग के बीच इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की लागत को साझा करने के लिए एक लागत साझाकरण तंत्र विकसित किया जा सकता है। इनक्यूबेशन से पहले और इनक्यूबेशन के बाद के चरणों के दौरान भी नवोद्यमों को सहायता प्रदान की जा सकती है। उदाहरण के लिए, राज्य सरकार विशिष्ट उच्च तकनीक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार चुनौती कोष शुरू कर सकती है। यह कोष ऐसे स्टार्ट–अप इनोवेटर्स और निर्माताओं को लक्षित कर सकता है जिनके पास पहले से ही ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जिनका अभी तक व्यावसायीकरण नहीं हुआ है। यह इस क्षेत्र में एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को प्रोत्साहित कर सकता है।

औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने में उच्च तकनीक वाले पूंजीगत सामानों की उल्लेखनीय भूमिका को देखते हुए, इस क्षेत्र में निर्माताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा नवोन्मेष (इनोवेशन) वाउचर की अवधारणा भी शुरू की जा सकती है। नवोन्मेष वाउचर से तात्पर्य निजी व्यवसायों की अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं, कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोगी आर एंड डी परियोजनाओं को सहायता और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए रियायती क्रेडिट लाइनों या अनुदान के रूप में सरकारों द्वारा प्रदान की गई धनराशि से है। यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने यह योजना शुरू की है जिसमें एमएसएमई किसी अभिनव विचार के व्यावसायीकरण के लिए पेशेवर कौशल, सेवाओं या तकनीकी जानकारी के लिए वित्त प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदनों का मूल्यांकन विचार/नवोन्मेष की आवश्यकता, नवोन्मेष से पड़ने वाले प्रभाव का स्तर और उससे होने वाले लाभ, वित्तीय व्यवहार्यता, नवोन्मेष से प्राप्त होने वाले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और विशेषज्ञ सेवा प्रदाताओं द्वारा उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता जैसे मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इस योजना के लक्षित संस्थान सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संस्थान, उच्च शिक्षा संस्थान, एसएमई, शोधकर्ता और वित्तपोषण संगठन हो सकते हैं। इसका उद्देश्य इनके बीच संस्थागत संबंध विकसित करने के साथ–साथ परामर्श, अनुसंधान और विकास

सहयोग स्थापित करना है। वाउचर एसएमई के लिए नवाचार से संबंधित समाधानों की मांग करने वाली शैक्षणकि संस्थाओं से संपर्क करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। जबकि वित्तपोषण आम तौर पर नवाचार / विचार को आगे बढ़ाने के लिए सेवा प्रदाताओं से सेवाएं लेने हेतु आवेदन करने वालों को प्रदान किया जाता है। कुछ देशों में आंतरिक रूप से कोई पात्र परियोजना शुरू करने की क्षमता रखने वाले आवेदकों को भी वित्त प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत सफल आवेदकों को 20: 80 (आवेदक और सरकारी वित्तपोषण का अनुपात) का निवल नकद सह–निवेश प्रदान करने में सक्षम होना जरूरी है।

चीन में चेंगदू और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो जैसे उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की तरह बंदरगाहविहीन हैं और फिर भी सफल हैं। राज्य में इसे अपनाने के लिए संभावित मॉडल भी हो सकते हैं। पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण के लिए ऐसे उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की स्थापना के लिए राज्य में उपयुक्त जिलों को चिह्नित किया जा सकता है। इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस, सुदृढ़ अवसंरचना और राजकोषीय प्रोत्साहनों पर विचार किया जा सकता है।

पर्यटन क्षेत्र का विकास

कई पर्यटन स्थलों का पर्यावरण, वहां का समाज और सौंदर्य उनकी अपनी लोकप्रियता के चलते संकट में आ गया है। यह संकट पर्यावरणीय गिरावट, सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा, बुनियादी ढांचे के अति प्रयोग या पर्यटकों के अनुभव में गिरावट के रूप में हो सकता है। यह विशेष रूप से आगरा जैसे शहरों में एक चुनौती है जहां पर्यटकों की संख्या उल्लेखनीय रूप से बहुत अधिक है। राज्य को टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने वाली रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। यह विशेष रूप से भीड़भाड़ के संबंध में, शारीरिक दूरी बनाए रखने के "नए सामान्य" के प्रकाश में और भी जरूरी हो जाता है। शुरुआत में एक डेटा सिस्टम की स्थापना करने पर विचार किया जा सकता है, जिसका उपयोग गंतव्यों की वहन क्षमता, पार्किंग और

होटल की उपलब्धता पर लाइव आंकड़े प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। पर्यटन अधिकारी पर्यटकों की संख्या को सीमित करने या आरक्षण प्रणालियों का उपयोग करने के लिए दैनिक सीमा का भी उपयोग कर सकते हैं।

राज्य में पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन स्थलों पर अपर्याप्त सहायता अवसंरचना, स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों की कमी सहित पर्यटन स्थलों पर अपर्याप्त स्वच्छता, प्रमाणित पर्यटक गाइडों की सीमित उपलब्धता, पर्यटन स्थलों पर स्वच्छ एवं गुणवत्ता वाले भोजनालयों की सीमित उपलब्धता, स्थलों पर अपर्याप्त आगंतुक प्रबंधन प्रणालियों, विशेष रूप से धार्मिक स्थलों पर अपर्याप्त आगंतुक प्रबंधन प्रणालियों के कारण विरासत स्थलों के संरक्षण में चूक और बदमाशों द्वारा पर्यटकों के उत्पीड़न के कारण भी प्रभावित होता है। इन चुनौतियों को कम करने के लिए, राज्य में महत्त्वपूर्ण स्मारकों और अविकसित पर्यटन स्थलों के रखरखाव और विकास के लिए एक विरासत विकास कोष स्थापित किया जा सकता है।

कौशल विकास

निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नवीनतम वैश्विक विकास अर्थात् निर्यात वित्त, बीमा, पैकेजिंग / ईकोलेबलिंग, गुणवत्ता आदि का गहन ज्ञान होना चाहिए। उन्हें आयात करने वाले देशों के नियमों और प्रक्रियाओं से खुद को परिचित करने की भी आवश्यकता है। इसलिए, राज्य में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न पहलुओं और विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से कार्यशालाओं / सेमिनारों / सम्मेलनों का आयोजन करने की आवश्यकता है। निर्यात संवर्धन परिषदों और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन जैसे संस्थानों के साथ एक व्यापक अंतर–मंत्रालयी नेटवर्क बनाया जा सकता है, जो तकनीकी उन्नयन और कौशल विकास के लिए एक समग्र परिवेश प्रदान करेगा, राज्य विश्वविद्यालयों को राज्य से मूल्य वर्धित निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित कौशल गैप को भरने के लिए व्यावसायिक और अनुसंधान–आधारित पाठ्यक्रम, दोनों शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

हिडन चैंपियंस पहल

राज्य सरकार एक 'हिडन चैंपियंस' पहल भी शुरू कर सकती है, ताकि ऐसे संभावनाशील छोटे उद्यमों को चिह्नित किया जा सके और उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके, जिन्होंने अभिनव पद्धतियों के माध्यम से उत्पादों के निर्यात में अनुकरणीय काम किया है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है। हिडन चैंपियंस पहल के तहत, चुनिंदा कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी एसएमई को इनक्यूबेट करने के लिए वित्तीय और गैर–वित्तीय दोनों प्रकार की सहायता मिल सकती है।

राज्य निर्यात पुरस्कार में संशोधन

राज्य निर्यात पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 क्षेत्रों में राज्य के उत्कृष्ट निर्यातकों को दिया जाता है। इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, इन 25 क्षेत्रों को 10 व्यापक क्षेत्रों में समेकित करने पर विचार किया जा सकता है। इन क्षेत्रों के भीतर, विभिन्न श्रेणियों जैसे अभिनव उत्पाद, नया बाजार, गुणवत्ता वाले उत्पाद, गुणवत्ता विनिर्माण प्रक्रिया आदि के तहत पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। यह उद्यमियों को सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस तरह का विभाजन टर्नओवर (एमएसएमई, बड़ी इकाइयों, ग्रासरूट व्यवसाय), नई कंपनियों और महिला उद्यमियों जैसे मापदंडों के आधार पर भी किया जा सकता है।

ब्रांड निर्माण

एमएसएमई को सीधे अपने बाजारों और ग्राहकों से जोड़ना फायदेमंद हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 'साथी' नाम से एमएसएमई के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च करने के साथ इस दिशा में एक कदम उठाया है। एमएसएमई द्वारा ई–कॉमर्स चैनल के प्रभावी उपयोग के लिए एक प्रभावी मार्केटिंग और ब्रांड निर्माण रणनीति आवश्यक होगी।

व्यवसाय अनुकूल अवसंरचना को सुदृढ़ करना

राज्य द्वारा व्यवसाय अनुकूल अवसंरचना में मौजूदा गैप को दूर कर अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक के अनुसार, परिवहन कनेक्टिविटी पैरामीटर (चार्ट 9) की सभी श्रेणियों में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन कमजोर है। यह इस पैरामीटर (चार्ट 10) पर सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम स्कोर में से एक है। जाहिर है, राज्य के लिए अधिक आईसीडी, एयर कार्गो सुविधाओं की स्थापना और बंदरगाहों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार कर इस प्रमुख पैरामीटर पर सुधार करने की काफी गुंजाइश है।

चार्ट 9: ईपीआई के परिवहन कनेक्टिविटी पैरामीटर पर उत्तर प्रदेश का स्कोर

परिवहन कनेक्टिविटी	**34.70**	
एयर कार्गो सुविधाओं से कवर्ड क्षेत्र	0	●
LEADS सूचकांक	0	●
ICDs से कवर्ड क्षेत्र	85.08	●
मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स केंद्र	0	●

नोटः सभी स्कोर 0 –100 के मानदंड पर हैं। लाल रंग पैरामीटर पर कम प्रदर्शन को इंगित करता है

स्रोतः निर्यात तत्परता सूचकांक 2021, नीति आयोग

चार्ट 10: राज्य–वार परिवहन कनेक्टिविटी स्कोर

नोटः बेंचमार्किंग अविभाजित राज्य जम्मू–कश्मीर के लिए की गई थी

स्रोतः निर्यात तत्परता सूचकांक 2021, नीति आयोग

उत्तर प्रदेश को आवश्यक निर्यात अवसंरचना के विकास और इसे सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार की निर्यात संबंधी व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) के तहत प्रदान की गई सहायता के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य में निर्यात अवसंरचना के विकास के लिए टीआईईएस के अंतर्गत केवल 1 परियोजना अनुमोदित की गई है।

राज्य में वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। यद्यपि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, तथापि डेयरी के लिए कोल्ड चेन अवसंरचना की उपलब्धता दुर्लभ है। उत्तर प्रदेश में देश में बल्क मिल्क चिलर का केवल 2 प्रतिशत, चिलिंग सेंटर का 8.6 प्रतिशत और डेयरी संयंत्रों का 5.1 प्रतिशत हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के डेयरी क्षेत्र में कोल्ड

चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत है। कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की पीएम किसान संपदा योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

एसपीएस/टीबीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर

निर्यात को बढ़ावा देने में व्यापार संबंधी अवसंरचना के अलावा, एसपीएस / टीबीटी अवसंरचना की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। अत्यधिक विनियमित उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिस्पर्धा के लिए, निर्यातों में विभिन्न गुणवत्ता अपेक्षाओं का पालन करने की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में, अनुसंधान संस्थान और एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं[9]।

देश के शीर्ष 5 निर्यातक राज्यों में शामिल होने के बावजूद, एनएबीएल मान्यता प्राप्त अनुसंधान प्रयोगशालाओं की उपलब्धता के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन महाराष्ट्र जैसे प्रतिस्पर्धी राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, जहां 895 मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य स्तर पर केवल 83 प्रयोगशालाएं हैं। राज्य में और अधिक एसपीएस/टीबीटी अवसंरचना स्थापित करने की आवश्यकता है।

राज्य में सौर सेल /मॉड्यूल विनिर्माण को बढ़ावा

इस सदी की शुरुआत से, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, विशेष रूप से सौर ऊर्जा खंड में काफी प्रगति की है। हालांकि, भारत सौर सेल के विनिर्माण में पीछे है, और परिणामस्वरूप, फोटोवोल्टिक सेल्स के व्यापार में भारी कमी है। इस प्रक्रिया में भारत आयात के लिए चीन पर निर्भर है।

उत्तर प्रदेश ने सौर ऊर्जा के लिए महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। राज्य में 30.27 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने की क्षमता है और सौर ऊर्जा

[9] निर्यात तत्परता सूचकांक, नीति आयोग

की उत्पादन क्षमता के लिए वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य 2,000 मेगावाट निर्धारित किया गया है। इससे राज्य में परियोजनाओं के लिए सौर सेल का पर्याप्त आयात होगा। आयात निर्भरता को कम करने के क्रम में, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के कार्यालयों में घरेलू रूप से विनिर्मित सौर उपकरणों के अनिवार्य उत्थान पर विचार किया जा सकता है। इस तरह के सार्वजनिक खरीद अवसरों के माध्यम से घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने से व्यापार घाटे को कम किया जा सकता है और निर्यात प्रतिस्पर्धा बनाने में भी मदद मिल सकती है।

क्लस्टरों को सुदृढ़ करना

ईपीआई में क्लस्टर के उप–स्तंभ में, उत्तर प्रदेश शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। क्लस्टर सुदृढ़ीकरण के मामले में इसका स्कोर 61 है, जबकि देश का औसत 36.25 है। यह राज्य को इन क्लस्टरों को बढ़ावा देने और अपने निर्यात में तेजी लाने का अवसर प्रदान करता है।

राज्य को अपने मौजूदा समूहों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जा सके और नए क्लस्टर विकसित करने के लिए क्षेत्रों / उपक्षेत्रों को चिह्नित किया जा सके। इस तरह के मूल्यांकन में मौजूदा बुनियादी ढांचे की बाधाओं के साथ–साथ तकनीकी उन्नयन, कुशल मानव संसाधनों तक पहुंच, पर्यावरणीय स्थिरता आदि में चुनौतियों से संबंधित पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। क्लस्टरों के आकलन के लिए राज्य द्वारा इस तरह की पहल को मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) योजना के तहत सहयोग प्रदान किया जा सकता है। क्लस्टरों के मूल्यांकन पर, राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक क्षमता निर्माण गतिविधियों को शुरू किया जा सकता है, जिसमें भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण / उन्नयन, संस्थानों का निर्माण, गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशालाओं की स्थापना, कॉमन सुविधा केंद्रों, डिजाइन केंद्रों और मानव संसाधनों का विकास शामिल है। राज्य सरकार सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश लघु से मध्यम अवधि में 30 बिलियन यूएस डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर सकता है। हालांकि जिन क्षेत्रों में राज्य पारंपरिक रूप से मजबूत है, वे निर्यात के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण बने रहेंगे। तथापि, राज्य से निर्यात के लिए निर्यात उत्पादों में विविधता लाने की जरूरत है। लघु से मध्यम अवधि में, निर्यात रणनीति में उत्पाद "चैंपियन क्षेत्रों" पर फोकस किया जाना चाहिए, जहां राज्य के पास तुलनात्मक लाभ है। इसके साथ ही, राज्य को अंडरअचीवर उत्पादों में क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है, जहां वैश्विक बाजार की मांग बढ़ रही है, लेकिन राज्य का निर्यात वर्तमान में प्रतिस्पर्धी नहीं है।

अनुलग्नक 1: उत्तर प्रदेश के लिए शीर्ष 10 उत्पाद चैंपियन के शीर्ष निर्यात गंतव्य और शीर्ष आयातक

एचएस कोड	एचएस विवरण	निर्यात गंतव्य	उत्तर प्रदेश का निर्यात (मिलियन यूएस डॉलर)	उत्तर प्रदेश के निर्यात में हिस्सेदारी	शीर्ष आयातक	आयात मूल्य (मिलियन यूएस डॉलर)	विश्व आयात में हिस्सेदारी
851712	सेलुलर नेटवर्कों या अन्य वायरलेस नेटवर्कों के लिए टेलीफोन	संयुक्त अरब अमीरात	1052.9	39.6%	संयुक्त राज्य अमेरिका	61659.0	19.0%
		रूस	320.9	12.1%	हांगकांग	45636.6	14.1%
		जर्मनी	194.2	7.3%	संयुक्त अरब अमीरात	23392.3	7.2%
		दक्षिण अमेरिका	128.2	4.8%	जापान	17984.8	5.6%
		संयुक्त राज्य अमेरिका	110.6	4.2%	जर्मनी	12924.8	4.0%
		विश्व	2658.8	100.0%	विश्व	323997.8	100.0%
020230	फ्रोज़न, बोवाइन पशुओं का बोनलेस मांस	मिस्र	458.4	27.2%	चीन	10630.2	37.9%
		वियतनाम	226.8	13.4%	संयुक्त राज्य अमेरिका	2593.7	9.3%
		मलेशिया	223.1	13.2%	जापान	1504.7	5.4%
		इंडोनेशिया	211.8	12.5%	दक्षिण कोरिया	1327.4	4.7%
		इराक	147.2	8.7%	हांगकांग	1280.0	4.6%
		विश्व	1688.6	100.0%	विश्व	28026.9	100.0%

एचएस कोड	एचएस विवरण	निर्यात गंतव्य	उत्तर प्रदेश का निर्यात (मिलियन यूएस डॉलर)	उत्तर प्रदेश के निर्यात में हिस्सेदारी	शीर्ष आयातक	आयात मूल्य (मिलियन यूएस डॉलर)	विश्व आयात में हिस्सेदारी
732690	लौह या इस्पात की वस्तुएं (लौह या इस्पात वायर या कास्ट वस्तुओं को छोड़कर)	संयुक्त राज्य अमेरिका	250.0	57.0%	संयुक्त राज्य अमेरिका	5445.7	10.1%
		ब्रिटेन	33.8	7.7%	जर्मनी	4660.6	8.6%
		नीदरलैंड	26.6	6.1%	मेक्सिको	3082.6	5.7%
		जर्मनी	21.4	4.9%	थाईलैंड	3037.3	5.6%
		सऊदी अरब	11.3	2.6%	फ्रांस	2178.8	4.0%
		विश्व	438.3	100.0%	विश्व	54037.2	100.0%
640391	एंकल कवर्ड अन्य फुटवेयर	ब्रिटेन	98.0	22.0%	संयुक्त राज्य अमेरिका	4150.0	27.8%
		संयुक्त राज्य अमेरिका	75.9	17.0%	जर्मनी	1581.4	10.6%
		जर्मनी	68.8	15.4%	नीदरलैंड	893.5	6.0%
		नीदरलैंड	31.9	7.1%	फ्रांस	855.7	5.7%
		पोलैंड	31.4	7.0%	इटली	750.4	5.0%
		विश्व	446.5	100.0%	विश्व	14926.8	100.0%

एचएस कोड	एचएस विवरण	निर्यात गंतव्य	उत्तर प्रदेश का निर्यात (मिलियन यूएस डॉलर)	उत्तर प्रदेश के निर्यात में हिस्सेदारी	शीर्ष आयातक	आयात मूल्य (मिलियन यूएस डॉलर)	विश्व आयात में हिस्सेदारी
760110	एल्यूमीनियम–मिश्र धातु नहीं	दक्षिण कोरिया	159.8	39.1%	संयुक्त राज्य अमेरिका	5214.8	14.2%
		वियतनाम	64.7	15.8%	चीन	4076.1	11.1%
		ताइवान	62.3	15.2%	तुर्किये	3536.6	9.7%
		चीन	54.4	13.3%	जापान	3504.7	9.6%
		थाईलैंड	26.1	6.4%	दक्षिण कोरिया	2988.5	8.2%
		विश्व	409.1	100.0%	विश्व	36629.9	100.0%
100630	अर्ध/पूर्ण रूप से मिलाए हुए चावल चाहे पॉलिश किए गए हों या चमकीले हों	नेपाल	152.2	47.9%	चीन	1247.5	5.7%
		संयुक्त अरब अमीरात	29.1	9.1%	फ़िलीपींस	1081.2	5.0%
		ब्रिटेन	16.0	5.0%	सऊदी अरब	1030.5	4.7%
		कतर	10.3	3.3%	बांग्लादेश	980.7	4.5%
		सऊदी अरब	8.5	2.7%	संयुक्त राज्य अमेरिका	952.2	4.4%
		विश्व	318.0	100.0%	विश्व	21763.3	100.0%

एचएस कोड	एचएस विवरण	निर्यात गंतव्य	उत्तर प्रदेश का निर्यात (मिलियन यूएस डॉलर)	उत्तर प्रदेश के निर्यात में हिस्सेदारी	शीर्ष आयातक	आयात मूल्य (मिलियन यूएस डॉलर)	विश्व आयात में हिस्सेदारी
100199	अन्य गेहूं और मेस्लिन	बांग्लादेश	214.4	63.3%	इंडोनेशिया	3548.4	7.6%
		इंडोनेशिया	37.6	11.1%	तुर्किये	2518.2	5.4%
		नेपाल	33.9	10.0%	ईरान	2486.5	5.3%
		दक्षिण कोरिया	23.2	6.9%	बांग्लादेश	1957.9	4.2%
		फ़िलीपींस	20.4	6.0%	फ़िलीपींस	1949.5	4.2%
		विश्व	338.9	100.0%	विश्व	46758.5	100.0%
290611	मेंथॉल	चीन	190.0	75.8%	चीन	311.5	37.0%
		संयुक्त राज्य अमेरिका	13.9	5.6%	संयुक्त राज्य अमेरिका	86.3	10.2%
		फ्रांस	7.5	3.0%	सिंगापुर	41.0	4.9%
		सिंगापुर	7.0	2.8%	इंडोनेशिया	30.9	3.7%
		जापान	6.1	2.4%	थाईलैंड	26.9	3.2%
		विश्व	250.6	100.0%	विश्व	841.9	100.0%

एचएस कोड	एचएस विवरण	निर्यात गंतव्य	उत्तर प्रदेश का निर्यात (मिलियन यूएस डॉलर)	उत्तर प्रदेश के निर्यात में हिस्सेदारी	शीर्ष आयातक	आयात मूल्य (मिलियन यूएस डॉलर)	विश्व आयात में हिस्सेदारी
170114	कच्ची गन्ना चीनी, ठोस रूप में, जिसमें अतिरिक्त स्वाद और रंग न मिले हों	इंडोनेशिया	116.5	45.7%	इंडोनेशिया	2229.9	14.9%
		बांग्लादेश	60.0	23.5%	चीन	1942.6	12.9%
		संयुक्त अरब अमीरात	21.0	8.2%	संयुक्त राज्य अमेरिका	1287.2	8.6%
		सऊदी अरब	17.9	7.0%	नाइजीरिया	901.2	6.0%
		यमन	17.5	6.9%	मलेशिया	813.1	5.4%
		विश्व	254.8	100.0%	विश्व	15014.7	100.0%
420100	पशुओं के लिए सैडलरी और हार्नेस	संयुक्त राज्य अमेरिका	55.1	22.3%	संयुक्त राज्य अमेरिका	767.4	30.4%
		जर्मनी	50.5	20.4%	जर्मनी	264.2	10.4%
		ब्रिटेन	27.5	11.1%	ब्रिटेन	172.2	6.8%
		नीदरलैंड	25.6	10.3%	नीदरलैंड	139.2	5.5%
		फ्रांस	18.0	7.3%	फ्रांस	119.4	4.7%
		विश्व	247.7	100.0%	विश्व	2528.5	100.0%

नोटः 1. उत्तर प्रदेश का निर्यात 2021–22 के लिए है, जबकि वैश्विक आयात 2021 के लिए है।

2. बोल्ड में चिह्नित देश वे हैं जो उत्पाद के संबंध में उत्तर प्रदेश के लिए शीर्ष निर्यात स्थलों में शामिल नहीं हैं।

स्रोतः डीजीसीआईएस, आईटीसी ट्रेड मैप, एक्ज़िम बैंक रिसर्च

इंडिया एक्ज़िम बैंक
India Exim Bank

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई-400005.
फोनः (9122) 22172600 | फैक्सः (9122) 22182572
ईमेलः ccg@eximbankinida.in | वेबसाइटः www.eximbankindia.in, www.eximmitra.in

Follow us on: